दिनांक 4 सितम्बर, 1985

सं ग्रों विं /रोहतक/132-85/36184. चूं कि हैरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मैं श्री राम सिनेबेटिवल, फैब्रिकस माड में इण्डस्ट्रीयल ऐरिया फ़ेस-1, बहादुरगढ़ के श्रीमक श्री गिरिजा शंकर तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई ग्रोद्योगिक विवाद है :--

ग्रीर चूकि हरियाणा के राज्यपाल किवाद को व्ययनिर्णत हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समुझते हैं;

इसितए, ग्रब, श्रौद्योगिक विवाद प्रधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड़ (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी ग्रिधिसूचना सं० 9641-1 श्रम/ 78-32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी ग्रीधिसूचना की धारा 7 के ग्रिधीन गठित श्रम न्यायालय रोहतक की विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे राज्यधित नीचे लिखा माकला न्यायनिर्णन एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रीमक के बीच या ती विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है:-

नया श्री गिरिजा शंकर की सेवाओं का समापन न्वायोजित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हक्षदार है ?
सं० ग्रो० वि०/एफ.डी./86-85/36191.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मैं० कास्ट-ई-कुला, प्लाट
नं०.108 सनटर-6, फरीदाबाद के अमिक श्री राम सुरेसन तथा उसके प्रवन्धकों के कध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में
कोई ग्रौद्योगिक विवाद हैं ;

ग्रीर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद की त्यावितर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसिनए, अब, अनैद्यौगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शिक्तयों का अयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना नं० 5415-3%म-68/15245, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए, अधिसूचना सं० 11495-जी-अम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उन्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित अम न्यायालय फरीदाबाद की विवादप्रस्त या उससे सुसंगत या उसने संसोधित नीचेलिखा मामला न्यायानिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उनते प्रबन्धकों, तथा श्रीमक के बीच या तो विवादप्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अधवा संबन्धित मामला हैं:--

न्या श्री राम सुरेमन की सेवाश्रों का समापन न्यायोजित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो बह किस राहत का इकदार है। सं० श्रो॰ वि०/एफ. डी./86-85/36198.—चुंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि भैं० श्रास्ट-ई-कुला, जाट नं०.108, सैक्टर-6, फरीदाबाद के श्रमिक श्री राम प्रसाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित नामले में कोई श्रीद्योगिक विवाद है;

भौर चुंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को त्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हें ;

इसलिए, अब, औबुयोगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियापा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी धिधमूचना सं० 5415-3-अम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-अम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचता की धारा 7 के अधीन गठित अम न्यायालम फरीदाबाद की विवादग्रस्त या उक्तसे सुसंगत भा उससे संबोधित नीचे लिखा मामला न्यायानिर्णय एवं पंचाट तीन मास मे देने हेंचु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा अमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबन्धित सामला है :---

क्या श्री राम प्रसाद की सेवाम्रों का समापन न्यांयोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है रि सं. थो. वि. /एफ.डी. /86-85/36205. — चूं कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं. कास्ट-ई-कुला, प्लाट नं०. 108, सैक्टर-6, फरीदाबाद के श्रमिक सुरेक प्रसाद यादव तथा उसके प्रबन्धकों के सध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई मौद्योगिक विवाद है;

ग्रीर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद की न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, और्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों को प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल र के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 541533-अम-57/15254, दिनांक 20, जून 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं 11495-जी-अम-57/11245, दिनांक 7फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित अम न्यायालय फरीदाबाद की विवादप्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबोधित नीचे लिखा मामला न्यायानिर्णय एवं पचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा अमिकों के बीच या तो विवादप्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अधवा संबन्धित मामला है :—

क्या श्री सुरेश प्रसाद यादव की सेवाओं का समापत न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?